



मुरैना जिले का कृषि प्रतिरूप : समस्यायें एवं समाधान

अजय सिंह सिकरवार

शोध छात्रा शा.एम.एल.बी. उत्कृष्ट महाविद्यालय ग्वालियर

डॉ.अतीन्द्र सिंह तोमर

विभागाध्यक्ष भूगोल डॉ. भगवत सहाय शा.महाविद्यालय ग्वालियर

KEYWORDS :

भोजन, वस्त्रा और आवास मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकतायें हैं इनमें भोजन तो जीवन का आधार है। भोजन आपूर्ति का साधन है कृषि। कृषि भारतीय जीवन, संस्कृति एवं अर्थ का आधार है। कृषि इस देश का प्रमुख व्यवसाय है। मुरैना जिले का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। इस जिले के भौगोलिक परिषेप ने भी कृषि को प्रोत्साहित किया है। मुरैना में कृषि व्यवसाय ही नहीं, अपितु धर्म एवं जीवन दर्शन है। इस क्षेत्रा का कृषक अपनी कृषिभूमि पर गर्व एवं गौरव का अनुभव करता है। किन्तु वर्तमान परिस्थितवष यहां के कृषक वडी संख्या में अपने इस परम्परागत व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। युवा पीडी की तो इस व्यवसाय में कोई रुचि नहीं है। इसका प्रमुख कारण इस व्यवसाय में दिनों - दिन वढता घाटा एवं वढती जनसंख्या, प्राकृतिक प्रकोप कृषि लागत का वढना आदि।

कृषि विकास का अर्थ है कि कृषि की निम्न उत्पादकत वाली परम्परागत पद्धति में परिवर्तन करमें उसे उच्च उत्पादकत से युक्त कर एक वैज्ञानिक एवं असधुनिक स्वरूप प्रदान करना है। वर्तमान समय में देश की वढती जनसंख्या को देखते हुये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है, ताकि वढती जनसंख्या के भरण - पोषण की व्यपस्था हो सके इसके लिये उद्यानिकी पफसलों का विस्तार किया जाय जिससे देश, राज्य, जिला आदि के कृषकों की आय में वृद्धि हो सके और कृषि घाटे के व्यवसाय के स्थान पर लाभदायक व्यवसाय में परिवर्तित हो सके। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिये आवश्यक है कि परम्परागत जीवन निर्वाह कृषि पद्धति के स्थान पर उद्यानिकी कृषि को बढावा दिया जाय।

अध्ययन क्षेत्रा

मुरैना जिला चम्बल संगम में मध्यप्रदेश के पश्चिमोत्तर कोने में स्थित है जो 25°22' उत्तरी अक्षां से 26°52' उत्तरी अक्षां तथा 76°10' से 78°42' पूर्वी दैान्तर के मध्य स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रा 4998.78 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 6 तहसीलें तथा 7 विकासखण्ड हैं। 2001 की गणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1592714 है जिले में 501686 हेक्टेयर क्षेत्रा पर कृषि की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य:-

अध्ययन में कृषि विकास में आने वाली समस्याओं को ज्ञात कर उनका समाधान निकालना।

अध्ययन क्षेत्रा में पारम्परिक कृषि घाटे का सोदा है। जिस कारण कृषक एवं मजदूर पलायन कर रहे हैं उन्हे उद्यानिकी कृषि जैसी लाभकारी व्यवसाय की जानकारी देकर पलायन से रोका जा सकता है।

खाद्यान्नों और व्यापारिक पफसलों के उत्पादन में वृद्धि की नवीन पद्धतियों को अपनाने के मार्ग में बाधों की पहचान करना तथा उनके समाधान हेतु उचित सुझाव देना।

उद्यानिकी पफसलों को लगाने के लिये कृषकों में जागरूकता लाना उद्यानिकी पफसलों के विकास के लिये उपयुक्त क्षेत्रा का चयन करना, पडती एवं बंजर भूमि में उद्यानिकी पफसले करने की सम्भावनाओं का पता करना। परिकल्पना:-

अध्ययन क्षेत्रा में निरंतर तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है जिस कारण भूमि पर प्रति व्यक्ति भार वढ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर कमी हो रही है। कृषक एवं मजदूर घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। अतः परम्परागत कृषि प्रतिरूप में बदलाव की आवश्यकता है। औषधीय कृषि लाभगारी व्यवसाय है। अतः कृषकों की आय में वृद्धि होगी, उनका घरों की तरफ पलायन रुकेगा, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

अध्ययन प्ति:-

अध्ययन को सरल, व्यवस्थित, वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जावेगा।

सर्वेक्षण :- अध्ययन क्षेत्रा में उद्यानिकी कृषि की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये क्षेत्रा का भ्रमण किया गया तथा अवलोकन एवं साक्षातकार द्वारा उद्यानिकी पफसलों के लिये उपयुक्त क्षेत्रा का चयन किया है।

समको संकलन :- अध्ययन में द्वितियक समको का संकलन विभिन्न ढासकीय, अढााकीय कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, संगठनों से किया गया है। उद्यानिकी कृषि से संबधित समको कृषि विभाग, कृषक प्रोक्षण केन्द्र, कृषि महाविद्यालय, कृषिपफार्म, सिंचाई विभाग कार्यालय भू अभिलेख आदि से संकलित किये गये हैं।

प्राप्त समको को सारणीबद्ध कर सांख्यिकी विधियों द्वारा विप्लेशन कर निश्कर्ष निकाले गये हैं।

मुरैना जिले का कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप

मुरैना जिले के भूमि उपयोग प्रतिरूप को सात श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

मुरैना जिले का भौगोलिक क्षेत्रापफल- मुरैना जिले का भौगोलिक क्षेत्रापफल 501686 हेक्टेयर है। जिसमें पोरसा विकास खण्ड का 54919 हेक्टेयर, अंबाह विकास खण्ड का 51122 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड का 106698 हेक्टेयर, जौरा विकास खण्ड का 66847 हेक्टेयर, पहाडगढ विकास खण्ड का 92495 हेक्टेयर कैलारस विकास खण्ड का 52115 हेक्टेयर सबलगढ विकास खण्ड का 77490 हेक्टेयर है।

वनक्षेत्रा- मुरैना जिले में 50669 हेक्टेयर क्षेत्रा में वन है। विगत 10 वर्षों में मुरैना जिले के वन क्षेत्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मुरैना जिले में वनों के मानक स्तर 33 प्रतिषत से कम वन पाये जाते हैं।

कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि- भूमि के इस संवर्ग के अन्तर्गत ऊसर भूमि, कृषि के लिये अनुपयुक्त भूमि, कृषि को छोडकर अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त भूमिक आती है मुरैना जिले में कृषि के लिये अनुपलब्ध भूमि 134504 हेक्टेयर है।

अन्य अकृषि भूमि, परती भूमि सम्मिलित नहीड - अन्य अकृषि भूमि के संवर्ग के अन्तर्गत मुस्तरकलित चारागाह तथा कृषि के लिये बेकार भूमि षड आती है। मुरैना जिले में अन्य अकृषि भूमि 19915 हेक्टेयर है इस संवर्ग की सर्वाधिक भूमि 4249 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड में है जो जिले की कुल अन्य अकृषि भूमि की 21.33 प्रतिषत है।

कृषि योग्य भूमि- कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत वह भूमि आती है, जिसमें कृषि नहीं की जाती है, किन्तु कुछ सुधार के उपरान्त कृषि सम्भव है। मुरैना जिले में कृषि योग्य भूमि 23556 हेक्टेयर है। जो कृषि योग्य भूमि की 39.96 प्रतिषत है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पहाडगढ विकास खण्ड में 9413 हेक्टेयर है। इस विकास खण्ड में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होने के कारण सिंचाई की समुचित सुविधों का आभाव तथा असमतल धरातल है।

परती भूमि- मुरैना जिले में परती भूमि 12913 हेक्टेयर है सबसे अधिक परती भूमि मुरैना विकास खण्ड में 4223 हेक्टेयर है जो जिले की कुल परती भूमि की 32क/70 प्रतिषत है सिंचाई सुविधों के अभाव अथवा भूमि की उर्वरता में वृद्धि के लिये कमी-कमी भूमि परती छोड दी जाती है।

पफसली क्षेत्रा- वर्तमान में जिस भूमि पर कृषि की जाती है, उसे पफसली क्षेत्रा कहते हैं। पफसली क्षेत्रा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- निरापफसली क्षेत्रा, द्विपफसली क्षेत्रा, कुल पफसली क्षेत्रा निरापफसली और द्विपफसली क्षेत्रा का योग कुल पफसली क्षेत्रा है।

निरापफसली क्षेत्रा- मुरैना जिले में 260129 हेक्टेयर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रापफल का 51.85 प्रतिषत है। सबसे अधिक निरापफसली क्षेत्रा 65196 हेक्टेयर मुरैना विकास खण्ड में है, जो जिले के कुल निरापफसली क्षेत्रा का 25.06 प्रतिषत है। इस विकास खण्ड की भौगोलिक विषलता तथा सिंचाई की समुचित सुविधों की उपलब्धता है।

द्विपफसली क्षेत्रा- जिस कृषि में दो पफसले पैदा की जाती है उसे द्विपफसली क्षेत्रा कहते हैं। दो पफसले, वर्षों सम्भव हैं, जहाँ सिंचाई की समुचित सुविधें उपलब्ध होती हैं। मुरैना जिले में 61336 हेक्टेयर क्षेत्रा द्विपफसली है, जो निरापफसली क्षेत्रा का 23 प्रतिषत है सर्वाधिक द्विपफसली क्षेत्रा मुरैना विकास खण्ड में 13049 हेक्टेयर है, जो जिले के कुल द्विपफसली क्षेत्रा का 21.28 प्रतिषत है, सबसे कम द्विपफसली क्षेत्रा पहाडगढ विकास खण्ड में 5171 हेक्टेयर है जो जिले के कुल द्विपफसली क्षेत्रा का 8.36 प्रतिषत है।

सकल पफसली क्षेत्रा- निरापफसली क्षेत्रा और द्विपफसली क्षेत्रा का योग सकल पफसली क्षेत्रा है। मुरैना जिले में सकल पफसली क्षेत्रा 321465 हेक्टेयर है, जो कुल

भौगोलिक क्षेत्र का 64.08 प्रतिषत है सर्वाधिक सकल पफसलीक्षेत्रा मुरैना विकास खण्ड में 78245 हेक्टेयर है। जो जिले के सकल पफसली क्षेत्रा का 24.34 प्रतिषत है सबसे कम सकल पफसली क्षेत्रा 34161 हेक्टेयर कैलारस विकास खण्ड में है जो जिले के सकल पफसली क्षेत्रा का 10.63 प्रतिषत है। मुरैना जिले में विभिन्न विकास खण्डों का भूमि उपयोग निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

समस्यायें :-

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्रा में आज भी पारम्परिक विधियों से कृषि की जा रही है। तथा सिंचाई सुविधों का विकास कम हुआ है। सिंचाई सुविधों की कमी के कारण उत्पादकता कम है क्षेत्रा में उर्वरकों का सुतुलित मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्नत किस्म के बीजों का भी कम प्रयोग किया जा रहा है। जिले में अपेक्षाकृत कम यंत्रोकरण हुआ है।

यहां विचारणीय तथ्य है कि निरन्तर वर्ष पर्यन्त कृषकों का खेतों में कार्य करने के वावजूद विपन्नता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कमी हो रही है। परिणाम स्वरूप कृषक कृषि कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसाय की ओर जा रहे हैं। या आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में सन 2007 से 2012 के बीच 3.2 करोड़ किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया है। तथा युवा पीढ़ी में तो इस व्यवसाय के प्रति कोई रुचि नहीं है। यदि यही स्थिति निरन्तर चली रही तो भारत में खाद्यानों पर अल्प निर्भरता समाप्त हो जायेगी और देश को एक गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पड़ेगा।

जीवन निर्वाह कृषि पद्धति के स्थान पर लाभदायक औषधिय कृषि, पफूलो, मसालो जैसी उद्योगिकी कृषि के लिये तैयार कर प्रशिक्षित करना होगा। कृषक उत्पाद को उचित मूल्य पर क्रय करने की भी व्यवस्था करनी होगी। अध्ययन क्षेत्रा में खण्ड भूमि का विस्तार चम्बल क्वारी और सांक नदियों घाटियों के समानान्तर एक से 06 कि.मी. चौड़ी पट्टी में पफेला है इस खण्ड भूमि में पहले कापफी मात्रा में प्राकृतिक बनस्पति के साथ औषधिय पोधे भी थे किन्तु बन विनाश के साथ ही औषधिय पोधे लुप्त होते जा रहे हैं। इस सम्पूर्ण खण्ड भूमि में पुनः औषधिय पोधे पफूलो के वृक्ष, पफूलो के पोधे तथा मसाले एवं सब्जियों की कृषि की जा सकती है। इससे इस क्षेत्रा का मृदा अपरदन रुकेगा तथा प्राप्त उत्पादन से कृषकों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी इसी प्रकार पहाडगढ एवं सबलगढ के बन क्षेत्रा में भी औषधिय एवं उद्योगिकी कृषि की जा सकती है। इन क्षेत्रा में वच, अर्जुन, बहेरा, सहजना, गिलोय, आदि औषधिय पोधे अन्ना, अमरुद, पपीता, नीबू, आम आदि पफूलो के पोधे गेंदा गुलब जैसे पफूलो के पोधे टमाटर, आलू, मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, बैंगन जैसी अनेक सब्जियां तथा मसालों की कृषि की जा सकती है। इसके लिये निम्न प्रयास करने होंगे।

1. जनजागृति-

औषधिय कृषि के महत्व के बारे में अध्ययन क्षेत्रा के कृषकों में जाग्रति होना अनिवार्य है। इसके आर्थिक लाभ एवं सामाजिक उपयोग के बारे में भी औषधियों को जानकारी होगी तब कृषक स्वतः ही इसकी कृषि करने लगेगा। समाज में सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये इतनी अनिवार्य प्राकृतिक औषधिय वनस्पति को मनुष्य अज्ञानतावश विलुप्त कर रहा है।

2. षासकीय प्रयास-

षासन एवं प्रषासन को औषधिय कृषि के विकास हेतु ग्राम स्तर पर प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाने तथा औषधिय कृषि के बीज सस्ते करने वाले कृषकों को इस कार्य हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

3. औषधिय उत्पाद हेतु बाजार का विकास-

षासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण अंचलों के ऐसे कृषकों जो औषधिय कृषि उत्पाद का विक्रय करना चाहें, आवश्यकतानुसार तुरन्त उन्हें वाजिव मूल्य मिल सके। नये बाजारों को विकसित करने तथा रिक्तता की पूति हेतु नये बाजार केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। नये बाजारों के स्थापना की वृषजमतप का आधार उपभोक्ता प्रमुखता, अभिगम्यता, केन्द्रीयता, परिवहन सुविध तथा बाजार केन्द्रों की स्थिति की उपयुक्तता होनी चाहिये।

4. दलाली प्रथा का समाप्त किया जाना-

कृषि पदार्थों के विपणन के साथ अभी भी दलाली प्रथा विद्यमान है इस प्रथा के कारण कृषकों के ऐसे उत्पाद कम मात्रा में होते हैं तथा उन पर आधारित उद्योग दूरस्थ अंचलों में होते हैं, दलालों के द्वारा वह नीची कीमत पर क्रय किया जाता है जिससे कृषकों को घाटा होता है। लागत अधिक लाभ कम होने से औषधिय कृषि उत्पाद के सन्दर्भ में दलाली प्रथा समाप्त कर सीधे षासकीय स्तर पर उचित मूल्य में खरीदी व्यवस्था किये जाने से लाभार्थ बढ़ेगा, जिसेस औषधिय कृषि की ओर लोगों का रुझान बढ़ेगा।

5. सूचना केन्द्रों का विकास-

यदि कृषकों को मूल्य स्तर, माल की आवक और अन्य सुविधयें जैसे मण्डी, षासकीय विपणन केन्द्र, कृषकों के लाभ हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं का संचयन आदि प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राथमिक सेवाओं जैसे डाकघर, तार ऑफिस आदि आनुपातिक ढंग से वितरित हों, ग्रामीण क्षेत्रा में समाचार पत्रों का नियमित वितरण तथा रेडियो एवं दूरदर्शन क्षेत्रा का विकास के द्वारा ये सुविधयें प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचलों में कृषक प्रषिक्षण तथा कार्यत्मक साक्षरता कार्यक्रम भी कृषकों को मूलभूत सूचनायें उपलब्ध करा सकता है। रेडियो द्वारा कृषि जगत कार्यक्रमों का प्रसारण कृषि एवं विपणन सुविधओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

6. अन्य संस्थागत कारक-

औषधिय कृषि के विकास के लिये किसी निश्चित समय तथा स्थान पर विनिमय पर आधारित कृषकों के भूमिका की उत्पादकता का निर्धारण तथा रोजगार सुविधयें उत्पन्न किये जाने की व्यवस्था के केन्द्रों का विकास आवश्यक है। ऐसे केन्द्र 5 या 10 ग्रामों के समूहों की स्थिति के अनुसार विकसित किये जाने चाहिए। विभिन्न सहायक संस्थायें जैसे स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल, स्थानीय स्वषासन एवं अन्य प्रषासकीय कार्यालय सामुदायिक केन्द्र, विद्युत आपूर्ति केन्द्र, सिंचाई के साधनों का विस्तार, औषधिय कृषि के लिये नवाचर केन्द्रों के स्थापन आदि की आवश्यकतानुसार मदद की जानी चाहिए।

मुरैना जिले में औषधिय कृषि के क्षेत्रा में लगभग न के बराबर विकास हुआ है किन्तु चम्बल, क्वारी, सांक का मध्यवर्ती उपजाऊ समतल मैदान चम्बल नहर से सिंचाई की सुविध तथा सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रा में विद्युत विस्तार के कारण विद्युत पम्पों से सिंचाई की सुविध, हरितक्रांति के प्रभाव, उपजाऊ मृदा, अनुकूल जलवायु सम्पूर्ण क्षेत्रा में सडकों के जाल के कारण नगदी, पफसलों के क्षेत्रा एवं उत्पादन में कापफी अधिक वृत्ति हुई है। उपरोक्त सभी सुविधयें औषधिय कृषि के लिये भी अनुकूल हैं। आवश्यकता केवल क्षेत्रा के कृषकों में औषधिय कृषि के प्रति जागृति की है। उनमें इस कृषि के महत्व तथा लाभ के बारे में जानकारी देने की है। उन्हें इस कृषि के बारे में प्रषिक्षण देने की है। पफर वह दिन दूर नहीं कि मुरैना जिला औषधिय कृषि के लिये सम्पूर्ण देश में जाना जायेगा।

उपरोक्त प्रयासों के द्वारा धीरे - धीरे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रा के कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तथा कृषि को घाटे के व्यवसाय से लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा बढ़ती बेरोजगारी एवं कृषि क्षेत्रा में पलायन को भी रोका जा सकेगा।

संदर्भ ग्रन्थ -

कुमार,प्रमिला : 1987 मध्यप्रदेश का प्रादेशिक भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, म.प्र. भोपाल।

चन्द्रा, वीरेन्द्र : 2003 सुगंधिय पौधों की खेती, कृषि सूचना एवं प्रकाषन निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधन, परिशद, नई दिल्ली।

चन्द्रा, वीरेन्द्र एवं: 2006 जड़ी-बूटियों की खेती, कृषि एवं सूचना प्रकाषन निदेशालय,

पाण्डेय, मुकुलचंद: भारतीय कृषि अनुसंधन परिशद नई दिल्ली।

चौहान, एन.एस.: 1997 औषधिय एवं सुगंधिय पौधों की खेती की आवश्यकता क्यों? उद्यमिता भोपाल ,म.प्र.द्व

जरयाल, गुरुपाल सिंह: 2001 व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त औषधिय पौधे, प्रथम से तृतीय संस्करणद्व सेडमैप प्रकाषन, भोपाल।

जरयाल, गुरुपाल सिंह: 1997 औषधिय पौधों की विपणन निर्देशिका ,तृतीय संस्करणद्व सेडमैप प्रकाषन भोपाल।

मौर्य, के, आर.: 2002 मसालों की खेती, सरोज प्रकाषन इलाहाबाद।

तिवारी,ज्वाला प्रसाद: 2001 औषधिय पौधे-कृषि एवं उपयोग, अभिनव प्रकाषन जबलपुर।

प्रतिवेदन एवं आलेख:

1. ग्वालियर राज्य 1912 ग्वालियर स्टेट गजेटियर वोल्यूम-1 स्टेण्डर्ड प्रेस इलाहाबाद।
2. ग्वालियर राज्य 1944 सेन्सस ऑफ इण्डिया वोल्यू-20 ग्वालियर सेन्सस कमिशनर अलीजाह दरबार प्रेस लखर।